



जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

छह राज्यों ने किया कानून लागू करने से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइजा, छात्र संगठन आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसु) सहित कई याचियों ने नागरिकता संशोधन कानून (कैब) की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिकाएं दायर कीं। इन अर्जियों में कहा गया है कि नागरिकता कानून में संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और समता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है।



गुवाहाटी में शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़।

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रह

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।



जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा रह कर दिया गया है। नागरिकता कानून को लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण 15-17 दिसंबर को

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में असम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू एवं निषेधाज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। विरोध प्रदर्शनों में तीन लोग मारे जा चुके हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी समेत

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर चिंता जताई।

अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का अनुरोध किया

खबरें पेज 13 पर



विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच विभिन्न राज्यों ने इसे लागू करने से मना करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब ने पहले ही मना कर दिया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वहां की उद्वेग सरकार में मंत्री बाला साहेब थोरट ने इस बाबत एलान किया। दूसरी

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने भी पकड़ी बंगाल, पंजाब और केरल की राह



राज्यों को इनकार का हक नहीं : केंद्र - खबरें पेज 8 पर

ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आशय की बातें बाकी पेज 8 पर

संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर हमला

हर बड़े आतंकी हमले के तार पाक से जुड़ते हैं

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भारत ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के हर बड़े कुकृत्य के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए आतंकवाद के इस पनाहगाह में प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर का मसला उठाए जाने और नागरिकता कानून का हवाला दिए जाने के बाद भारत ने

जब लोमड़ी, मुर्गी की रखवाली कर रही होती है तो हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होती है।

-पालोमी त्रिपाठी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव

पलटवार किया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने महासभा में 'शांति की संस्कृति' बाकी पेज 8 पर

राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार मामलों को लेकर कथित टिप्पणी पर शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने भारी हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।



राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है। - राजनाथ सिंह



यह बयान भारत की महिलाओं और देश का अपमान है। -स्मृति ईरानी

राहुल का माफी मांगने से इनकार

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (जनसत्ता ब्यूरो/भाषा)।

बलात्कार पर कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा के हमलों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर कभी माफी नहीं मांगने वाले।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'जहां तक माफी की बात है तो मैं कभी इनसे माफी मांगने वाला नहीं हूँ।' कांग्रेस नेता ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा- मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने क्या बोला। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'मेक इन इंडिया' होगा। हमने सोचा कि अखबारों में 'मेक बाकी पेज 8 पर

'मजबूत मालदीव के लिए भारत प्रतिबद्ध'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्क एवं द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक नतीजों पर संतोष जताया है और कहा कि भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक एवं मजबूत

मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात

भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक, मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। - नरेंद्र मोदी

मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने भारत- मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।



प्रधानमंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देने के लिए व्यापक चर्चा की। दोनों

मंत्रियों ने बिना किसी सहयोगी के वार्ता की। प्रधानमंत्री कार्यालय बाकी पेज 8 पर

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और गणना में मतों की संख्या में कथित विसंगतियों की जांच के लिए दो गैर सरकारी संगठनों की जनहित याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं को पहले

बाकी पेज 8 पर



कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंची भाजपा की महिला सांसद

आरंभ होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी के बयान से यह सदन और पूरा देश आहत हुआ है। 15 मिनट बाद सदन शुरू होने

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंची निर्भया की मां

जनसत्ता ब्यूरो/संवाददाता नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए पीड़िता की मां ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया। दिसंबर, 2012 के इस सनसनीखेज अपराध के चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से तीन मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अक्षय के अलावा तीन अन्य दोषियों के पास अभी भी शीर्ष अदालत में अपनी



सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई

एएसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि वे दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि पीड़िता की मां के वकील की बात भी 17 दिसंबर

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सबरीमला मंदिर में पुलिस की सुरक्षा में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत ही भावनात्मक विषय है और वह नहीं चाहता कि स्थिति विस्फोटक हो। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति सुर्य कांत

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में एक फैसला है। मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है। मैंने अभी तक वृहद पीठ गठित नहीं की है। सहूलियत के संतुलन के लिए जरूरत है कि हम आज कोई आदेश नहीं दें। - प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर किसी प्रकार बाकी पेज 8 पर

दरअसल



दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कड़ाके की ठंड मौसम की करवट जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बर्फबारी

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

जनसत्ता टीम नई दिल्ली/देहरादून 13 दिसंबर।

पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओले के साथ तेज बारिश होने से मौसम ने एकदम से करवट बदला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित तमाम इलाकों में इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश से प्रदूषण में भी कमी दर्ज हुई। उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी और उसके आसपास उंचाई वाले स्थानों पर शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से चल रही बर्फबारी शुक्रवार को भी जारी रही। कुछ दिनों



में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी

पश्चिमी विक्षोभ का असर

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई और ओले पड़े। तमाम पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है।

हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों से आ रही हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री कमी के साथ 21.8 दर्ज किया गया। पालम में 40.2 मिलीमीटर बारिश के साथ तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण पर्वत बर्फ से लकड़क हो गए हैं। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर, टिहरी चंपावत रुद्रप्रयाग समेत राज्य बाकी पेज 8 पर

रविवारी
15 दिसंबर, 2019

मानसिकता में खोटे

बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने की मंशा से कई कड़े प्रावधान किए गए, पर उनमें निरंतर बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह दूषित मानसिकता है। बता रही हैं नाज खान।

● कविता/ शंकरानंद ● कहानी/ विमल सेन सिंह ● ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ ● योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर ● शक्तिस्थल/ श्रीनिवास रामानुजन ● दाना-पानी/ मानस मनोहर ● सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दी और बेशुमार स्टाइल ● दीपति अग्रिवा ● कविता/ शिव मोहन यादव ● कहानी/ सुधा गुप्ता 'अमृता'



नागरिकता कानून के खिलाफ नागरिक संगठन सड़क पर उतरे

जामिया के युवाओं की पुलिस से झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में शुक्रवार को कई विरोध प्रदर्शन किए गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन तो हिंसक हो गया। छात्रों का मार्च रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय से निकलकर संसद भवन की ओर जाना चाह रहे थे। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने भी पथराव किया। पुलिस ने सड़क को घेर दिया तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए।

संसद मार्ग, जंतर मंतर पर जमघट रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के परामर्श के बाद ऐतिहासिक के तौर पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पटेल चौक और जनपथ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों को घंटो बंद कर दिया गया। देर शाम उन्हें फिर खोल दिया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले अरुणा राय, शंकर सिंह, और निखिल डे ने उम्मीद जताई कि सुप्रिम कोर्ट इस तरह से भारतीय संविधान के मूल ढांचे को कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने कहा-यह कानून भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है।

नागरिक संगठनों की ओर से रवि नायर, अनिल चमडिया, मौलाना अस्मगर अली, नवेद हामिद जफर महमूद, सलीम इंजीनियर आदि ने



जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संशोधन कानून देश को बांटने और अस्थिर करने वाला बताया। उन्होंने साझा बयान में कहा-यह देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने इसका विरोध किया और देश के राष्ट्रपति से अपील की कि वे इसपर अपनी सहमति न दें और पुनर्विचार के लिए इसे सदन में वापस भेजें। सोशलिस्ट युवजन सभा ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया। युवजन सभा की ओर से विशाल जोशी और प्रदीप साह ने कहा उनकी पार्टी इसपर सक्रिय आंदोलन करेगी। उन्होंने नागरिकों से सविधान्य अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की अपील की।

12 पुलिसकर्मी घायल

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि हादसे में 12 पुलिसकर्मीयों और अधिकारियों को चोटें पहुंची हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। दोनों को पास अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा भी जामिया पहुंचे। उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू गैस की निंदा की और देषियों पर कार्रवाई की मांग की।

कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा : आपको बस कमरों का क्रमांक पता

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर हैरानी जताई कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को उन विद्यार्थियों के अकादमिक व्यौरों की कोई जानकारी नहीं है जिनके खिलाफ उसने अवमानना की याचिका दायर की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन किया। न्यायमूर्ति एके

चावला ने विश्वविद्यालय से एक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें उन छात्रों के पाठ्यक्रम, उनकी स्थिति और परिसर में उनके रहने की अवधि की जानकारी देने को कहा गया है जिनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है। अदालत मामले पर सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगी। अदालत ने कहा, 'यह स्तब्धकारी है कि आप अवमानना का मामला दायर करते हैं लेकिन आपको विद्यार्थियों के बारे

कानून पर चुप्पी तोड़ें मुख्यमंत्री : सुभाष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की नीयत से यह विधेयक लेकर आई है, ताकि उसे इसका फायदा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधेयक पर एकदम से चुप्पी साध रखी है, जिससे जाहिर होता है कि अंदरखाने इसका समर्थन कर रहे हैं।

सुभाष चोपड़ा ने इस मामले पर ट्वीट के जरिए भी केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि एक रणनीति के तहत केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी ओर जनता को भ्रमित करने के लिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आधे-आधरे मन से विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेकर बीच का रास्ता लेते हुए बोलते हैं। वहीं, सीलमपुर में विधेयक के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने रैली निकाल विरोध जताया। इस दौरान अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि भाजपा धर्म निरपेक्षता पर बार-बार हमला कर रही है। पर देश ने कभी स्वीकार नहीं किया।

घर बैठे मिलेगा 30 और सरकारी सेवाओं का लाभ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जनता को दिल्ली सरकार की 30 और नई सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध होंगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाणपत्र, जांच समेत अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इन सेवाओं को डोर स्टेप डिजिटरी सिस्टम के तहत जोड़ा है। नई सेवाओं के शामिल होने बाद घर बैठे मिलने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। अब जनता को विभिन्न 14 विभागों की सेवाएं इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग साल भर पहले दिल्ली सरकार ने एक खास प्रयोग कर इस व्यवस्था को शुरू किया था। इस सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने एक कॉल सेंटर भी शुरू किया है। जिस पर जनता फोन करती है। इस व्यवस्था के जरिए किसी भी कागजात को बनवाने का तरीका अब जरूरी दस्तावेज फोन पर ही बना दिए जाते हैं। इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को घर बैठे ही प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन, डीटीसी, श्रम, बाल कल्याण, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की सेवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सवा

हिंसक प्रतिशोध की गाथा



मर्दानी- 2

रेटिंग- ★★

निदेशक- गोपी पुत्रन

कलाकार- रानी मुखर्जी विशाल जेटवा, जितु सेनगुप्ता, दीपिका अमीन, श्रुति बापना

साल 2014 में रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी मर्दानी। 'मर्दानी-2' उसी का सिक्वेल है। यह फिल्म महिलाओं के साथ हो रहे और बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर बनाई गई है। राजस्थान के कोटा को केंद्र बनाकर कहानी गढ़ी गई है। यहीं पर पोस्टेड है पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी)। और यहीं का है सनी (विशाल जेटवा) जो एक सीरियल रेपिस्ट है। सनी चालाक है, धूर्त है शातिर है और हृदयहीन है। उसे पकड़ना या कानून के फंदे में लाना आसान नहीं है। पर उसका सामना होता है एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी से जो न सिर्फ जांबाज है बल्कि महिलाओं के साथ होनेवाले किसी अत्याचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है। शिवानी सरेंआम उन लोगों की धुलाई करती है जो महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यहार करते हैं। क्या शिवानी ऐसे चालाक अपराधी को कानूनी शिकंजे में ले पाएगी?

इसमें संदेह नहीं कि 'मर्दानी-2' उस समय आई है जब महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर यह उस समय भी आई है जो पुलिस कानून अपने हाथ में लेकर उन लोगों का काउंटर करते हुए उनकी हत्याएं भी कर रही है जिनपर बलात्कारी होने के आरोप

है। हैदराबाद एक हालिया उदाहरण है। यह फिल्म भी पुलिस के कानून में हाथ में लेने और अपराधियों को अपनी तरफ से दंड देने की वकालत करती भी दिखती है। 'मर्दानी-2' हिंसक प्रतिशोध की कहानी भी है। क्या ऐसे हिंसक प्रतिशोध का समर्थन किया जाना चाहिए। यह सवाल भी उठता है। हम एक न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं या प्रतिशोध से भरा समाज। हालांकि इस तरह के संदेश कई फिल्मों में आए हैं और आते रहे हैं। इसलिए मर्दानी-2 में जो दिखाया गया है उसमें नया कुछ नहीं है। यहां हिंसक यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म यौन दुर्व्यवहार को जितनी संवेदनशील है उससे अधिक पुलिस द्वारा कानून को हाथ में लेने के समर्थन में खड़ी दिखती है।

रानी मुखर्जी पुलिस अधिकारी की भूमिका में जबर्दस्त रूप से दमदार हैं। कह सकते हैं कि ये फिल्म सिंधम जैसी फिल्मों की कड़ी में है जिसमें पुलिस अधिकारी को इमानदार के साथ साथ अपराधियों की दुकाई करनेवाला दिखाया जाता रहा है। रानी अब अपने करिअर से उस दौर में जहां वह किसी रोमांटिक भूमिका के लिए नहीं रह गई है, इसलिए पुलिस अधिकारी की भूमिका में ही लीड रोल में आ रही है। अब भी वे अपने चेहरों पर जजबत दिखाते में सक्षम हैं। जहां तक फिल्म के खलनायक विशाल जेटवा का मसला है वे एक नई खोज की तरह हैं। हालांकि वे टेलीविजन के जेजे माने कलाकार हैं पर अपने इस फिल्मी रूप में वे एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आते हैं जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी क्रूर यानी साइको है। बिना किसी पश्चाताप के अपराध करनेवाला।

अगिनकांड में मारे गए मजदूरों के लिए धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने पिछले दिनों अनाज मंडी के अवैध कारखाने में आगजनी से मारे गए तीस मैथिल मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। इसकी अगुआई राजेंद्र शर्मा और संचालन शिशिर कुमार झा ने किया।

समिति के संयोजक अमरेंद्र झा और शिशिर कुमार झा ने दिल्ली, बिहार सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से दस-दस लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। दोनों नेताओं ने पलायन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने पृथक मिथिला राज्य बनाकर मिथिला के सर्वांगीण विकास करवाने की अपील की। धरने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद रामप्रीत मंडल, दिल्ली कांग्रेस के अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद, गोपाल झा, विधायक संजीव झा आदि मौजूद थे।

आज के कार्यक्रम

रामा/संगोष्ठी
न्यू सोशलिस्ट इनेशिएटिव : हिंदी जगत और आधुनिकता विषय पर विचार गोष्ठी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयील उपाध्याय मार्ग, शनिवार शाम साढ़े पांच बजे।

‘नब्बे फीसद महिलाओं को पसंद है आप’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया कि दिल्ली की 90 फीसद महिलाएं आम आदमी पार्टी को पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मदद नहीं बल्कि मौका चाहिए। उनको मौका मिलता है तो वे सीधे चौका लगाती हैं। वे नई दिल्ली में फिक्की महिला संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को पसंद करने के लिए अलग- अलग तर्क दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में देश में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने खत हो सकता है तो महिलाओं को सुरक्षा भी दी जा सकती है, इसके लिए केवल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की पुलिस बहुत अच्छी है। केवल व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुफ्त बस सफर 88 फीसद महिलाओं को पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं, उसमें सिर्फ 11 फीसद महिलाएं बाहर काम करती हैं। मेट्रो में 33 फीसद ही महिलाएं और 67 फीसद पुरुष सफर करते हैं। डीटीसी में 30 फीसद महिलाएं व 70 फीसद पुरुष हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिलाओं को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। महिलाओं को भरोसा नहीं है कि पुलिस मदद देगी। उन्होंने कहा हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं अगर पुलिस को व्यवस्था को कहा जाए सुरक्षा दो, राजनीति नहीं चलेगी तो देगे। वह आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने कहा कि जब स्कूल व अस्पताल ठीक हो सकते हैं तो पुलिस भी ठीक किया जा सकता है।

मेडिकल स्टोर में लगवाई दो साल की बच्ची को सुई, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र में एक परिवार ने घर के पास के मेडिकल स्टोर में जाकर बिना डॉक्टर की सलाह के दो साल की बच्ची को दवा दी और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बच्ची को सर्दी-जुकाम हुआ था। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा का कहना है कि परिवार की शिकायत पर आरोपी स्टोर संचालक मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार जीटीबी एंक्लेव में रहता है। दो साल की बच्ची के पिता एक कारखाने में मजदूरी का

झुग्गी वालों को मकान देगा डीडीए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

झुग्गी कॉलोनियों में रहने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण 40 हजार मकान देगा। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये मकान विभिन्न 32 कैम्प के निवासियों को मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने 160 झुग्गी कैम्प को पक्का मकान बनाने के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बशर्णी समेत भाजपा ने अन्य नेता उपस्थित थे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि

चेन्नई के शख्स ने मेट्रो के आगे जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शुक्रवार को चेन्नई निवासी भगत शे (33) ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम भगत को पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह इन दिनों नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में

डीडीए द्वारा धनराशि जमा कराने के बावजूद 10 माह तक पक्का मकान देने के लिए सर्वे को रोककर रखा था और इसकी जगह मुख्यमंत्री योजना के तहत सर्वे शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर डीडीए ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा कि सरकार नियमों नजरअंदाज कर सर्वे करा रही है। इसे तुरन्त रोका जाए। इसके उपरांत 20 अगस्त, 2019 को डीडीए ने स्वयं सर्वे शुरू कर दिया। 185 डिप्लोमिब कैंपों को डीडीए के सर्वे के अन्दर जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि 5173 झुग्गीवासियों ने बैंक से लोन लेकर 68 हजार प्रति झुग्गी के हिसाब से दिल्ली सरकार को 39 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करवाए, फिर भी दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें कोई भी पक्का मकान नहीं दिया।

काम कर रहे थे और नोएडा के सेक्टर-128 में ही किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी परिवार को दे दी गई। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के आगे कूद गया है।

खोज

पुआल से विकसित करेंगे बिजली बनाने की स्वदेशी तकनीक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पुआल के बेहतर उपयोग व प्रदूषण का समाधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास ईंधन के रूप में धान के पुआल का उपयोग करके ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करेगा। आइआइटी का कहना है कि यह 'स्टबल बर्निंग' से निपटने के लिए अहम कदम होगा। पुआल खेतों में जलाने से मिट्टी की गंधन होता है। मिट्टी के फायदेमंद जीव नष्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी हानिकारक गैसों व प्रदूषक कणों (पीएम) को उत्सर्जन होता है।

अकेले पंजाब और हरियाणा में हर साल 35 मिलियन टन धान की पैदावार होती है, जो मवेशियों के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है।

खेतों में जलाया जा रहा है। लेकिन उसी पुआल में लगभग 3200 से 3500 किलो कैलौरी प्रति किलोग्राम का उपयोगी तापमान होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के लगभग बराबर होता है। सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड (एसएईएल) दो बायोमास-आधारित बिजली संयंत्रों का संचालन कर रहा है। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा पंजाब में। यह पंजाब में दो सौ फीसद धान के पुआल आधारित बिजली संयंत्रों को चालू करने की प्रक्रिया में है, इसके अलावा हरियाणा राज्य में एक ही ईंधन पर आधारित दो और बिजली संयंत्रों को शुरू करने की योजना है।

यह संयंत्र डेनमार्क की कंपनियों की ओर से प्रदान की गई तकनीक पर आधारित है व इसकी सीमाएं हैं। लिहाजा प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए और सुधार

की आवश्यकता है। इस मकसद के साथ कंपनी ने आइआइटी चेन्नई में 'नेशनल सेंटर फॉर कम्बिशन रिसेच एंड डेवलपमेंट' से साझेदारी की है ताकि अनुसंधान और विकासआत्मक गतिविधियों के संचालन में सहयोग किया जा सके। इसके लिए आइआइटी मद्रास में पुआल के जलने को बारीकी से देखने के लिए ब्यायलर लगाकर काम किया जाएगा। इसके आंकड़ों का विश्लेषण करके आगे का विकास किया जाएगा।

इसमें देखा जाएगा कि सुरक्षित ढंग से पुआल से बिजली कैसे बनाई जाए व क्या इसमें नगर निगम के ठोस कचरे को भी मिलाया जा सकता है। इस बारे में आइआइटी के प्रोफेसर ईंचां सत्यनारायण चक्रवर्ती ने कहा कि इसका परीक्षण पहले प्रयोगशाला में किया जाएगा इसके बाद पंजाब में ब्यायलर का नमूना बना कर वहां फील्ड परीक्षण किया जाएगा। इस पहल के फायदों पर प्रकाश डालते हुए सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड

के प्रबंध निदेशक जसवीर सिंह आवला ने कहा कि यह सहयोग पुआल जलाने की तकनीक को स्वदेशी बनाने और आयात से बचने के लिए किया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में हर साल उपलब्ध पुआल से लगभग 4000 मेगावाट बिजली संभव है। इसे ग्रीनहाउस गैसों के बिना उत्पन्न किया जा सकता है इसके अलावा भूमि को जलने से बचाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बिजली संयंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम संचालित करके कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर वी राघवन ने कहा कि बॉयलरों के परिचालन मापदंडों में भारत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। इसे बॉयलरों के उत्सर्जन में कमी लाने और लंबे समय तक चलाने में सक्षम बनाना होगा।

संकट के सामने

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से देश की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं वे तो चिंतित करने वाले हैं ही, साथ ही खुदरा महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, वे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। चूंकि महंगाई का मामला सीधे आमजन से जुड़ा है, इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है। महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। ऐसे में अगर यह पता चले कि नवंबर में खुदरा महंगाई पिछले चालीस महीनों में सबसे ज्यादा रही, तो होश उड़ने तय हैं। इस साल नवंबर में खुदरा महंगाई की दर 5.54 फीसद रही, जबकि अक्टूबर में यह 4.62 फीसद थी और पिछले साल नवंबर में 2.33 फीसद थी। यानी महीने भर में करीब एक फीसद महंगाई बढ़ी और पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा। छोटी-मोटी चीजों में महंगाई का भले पता न चले, लेकिन प्याज के दाम तो पिछले दो महीनों से लोगों के आंसू निकाल ही रहे हैं। खुदरा महंगाई बढ़ने का कारण खाद्य पदार्थों में तेजी बताया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो महंगी न हुई हो। मोटे अनाज से लेकर सब्जियां, अंडे, मांस-मछली, दालें सबने लोगों की जेब से ज्यादा पैसे निकाले।

बढ़ती महंगाई बता रही है कि उत्पादन से लेकर दुलाई तक की प्रक्रिया में लागत बढ़ रही है। इसलिए दाल-अनाज जैसी चीजों के दाम बढ़े हैं। पिछले साल जून में भी खुदरा मुद्रास्फीति पांच फीसद पर पहुंच गई थी। महंगाई चाहे थोक मूल्य सूचकांक आधारित हो या फिर खुदरा में, इसका सीधा असर तो बाजार और खरीदार पर पड़ता है। यों हमेशा मुद्रास्फीति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना बताया जा रहा है और ऐसा होता भी है। लेकिन इस बार तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले कुछ महीनों से एक स्तर पर ठहरे हुए हैं। ऐसे में खुदरा महंगाई बढ़ना हैरान करने वाला है। हालांकि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक कदम उठाता है। रिजर्व बैंक का लक्ष्य रहता है कि महंगाई दर चार प्रतिशत से ऊपर न निकले। लेकिन जब मुद्रास्फीति इससे ऊपर निकलने लगती है तो केंद्रीय बैंक पर नीतिगत दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है। इसका असर यह होता है कि बैंक कर्ज सस्ता होने के आसार कम हो जाते हैं और अभी अर्थव्यवस्था के रफ्तार देने के लिए कर्ज और सस्ता करने की दिशा में विचार चल रहा है। ऐसे में महंगाई कैसे रुके, यह बड़ा सवाल है।

सिर्फ महंगाई ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र में लंबे समय से जो सुरती बनी हुई है, उसका असर अब साफ दिख रहा है। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.8 फीसद की गिरावट बता रही है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की जो उम्मीदें बनी थीं, वे हवा हो गई हैं। हालांकि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए पिछले तीन महीनों में कई उपायों का एलान किया, जिनमें कारपोरेट करों में कटौती और बैंकों को पैकेज देने जैसे कदम भी शामिल हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखा। ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले क्षेत्र में लंबी मंदी ने हालात बिगड़ने के संकेत पहले से दे दिए थे, लेकिन सरकार ने कई महीनों तक इनकी अनदेखी की और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। उनका नतीजा आज सामने है। अब भले सरकार को नौद टूटी हो, लेकिन उद्योग क्षेत्र की हालत सरकारी आंकड़े बयां कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और घटता उत्पादन बता रहा है कि सरकार समय रहते नहीं चेती तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी।

पर्यावरण के लिए

करीब ढाई महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में स्वीडन की एक सोलह साल की किशोरी ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु संकट पर अपनी तीखी राय जाहिर करते हुए पर्यावरण संरक्षण के मामले में महज औपचारिकता निभाने को लेकर दुनिया के तमाम देशों को कठघरे में खड़ा किया था। तब उनके सख्त तेवर की भी काफी चर्चा हुई थी। अब भारत में मणिपुर की आठ साल की नन्ही बच्ची लिंसीप्रिया कंगुजम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ग्रेटा थनबर्ग की तरह ही इस नन्हीं कार्यकर्ता ने भी मैट्रिड में चल रहे ‘कॉप- 25’ सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से धरती, इंसानी नस्ल और उसके जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बिना देर किए कार्रवाई करने का आग्रह किया। कंगुजम अब तक इक्कीस देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्या पर अपनी बात रख चुकी हैं और उन्हें दक्षिणी गोलार्ध की ‘ग्रेटा थनबर्ग’ बताया जा रहा है। पर्यावरणविदों के बीच यह ख़ास आकर्षण का विषय है कि इतनी कम उम्र में यह बच्ची पारिस्थितिकी संतुलन के मसले पर कितना सरोकार रखती है। लेकिन सच यह है कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास की आबोहवा पर नजर रखता है और उसमें हो रहे बदलावों को करीब से महसूस कर पाता है तो वह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा थनबर्ग के साथ-साथ बारह देशों के पंद्रह अन्य युवा कार्यकर्ताओं ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने के लिए पांच देशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तब यह सवाल उठा था कि पिछले चार-पांच दशक से बढ़ते तापमान के मसले पर होने वाले वैश्विक सम्मेलनों में दुनिया भर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि आखिर किस तरह की कार्य-योजना पेश करते हैं कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। क्या इसी रुख के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा? सवाल है कि पर्यावरणविदों की राय जब सामने आती है तब दुनिया भर में इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन जब उससे बचने के उपायों की बात आती है, तब ख़ासतौर पर वे देश क्यों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। जाहिर है, यह मुख्य रूप से व्यवस्था का सवाल और इच्छाशक्ति के अभाव का मामला है।

इसलिए कंगुजम की यह बात महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि उसके जैसे नन्हे कार्यकर्ता व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन का संकट दूर होने का रास्ता अपने आप तैयार हो जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक सवालों पर केंद्रित अमूमन हर साल होने वाले सम्मेलनों के बावजूद हालत आखिर ऐसी क्यों है कि हर अगले वर्ष जलवायु के सामने खड़ी चुनौतियां गहरी होती जा रही हैं? दुनिया के जो देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ में आ रही है और इस मसले पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का दबाव क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्यों ऐसी नौबत आई है कि अब नई पीढ़ी के कम उम्र के बच्चों की भी नजर इस समस्या पर जा रही है और वे न केवल खुद अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल, पहले ग्रेटा थनबर्ग और अब लिंसीप्रिया कंगुजम जैसी किशोर और युवा कार्यकर्ताओं ने अब तक के वैश्विक पहलकदमियों को कठघरे में खड़ा किया है कि क्या केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताने भर से पर्यावरण की गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा!

कल्पमेधा

कविता मन की वह इच्छा है, जो हृदय को आह्लादित कर देती है।

- खलील जिब्रान

जनसत्ता

अरुण तिवारी

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी।

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी।

हम इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस वक्त की दो सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं- हताशा और तनाव। इन चुनौतियों के फलस्वरूप प्रमुखता से उभरते दृश्य चार हैं: अशांति, आत्मघात, विस्थापन और युद्ध। ये दृश्य पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं और काफी गंभीर व कष्टदायक हैं। संयुक्त राष्ट्र चिंतित है कि लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। उसकी चिंता यह भी है कि लोग एक देश से उजड़ कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं।

यूरोपीय शहरों के मेयर चिंतित हैं कि विस्थापित उनके यहां आकर क्यों बस रहे हैं। जहां एक ओर भूखे, बीमार, लाचार लाखों परिवार रोजगार और शांति की तलाश में अपनी जड़ों से उजड़ने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर जिन इलाकों में वे जाकर बस रहे हैं, वहां कानून-व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सांस्कृतिक तालमेल न बनने से भी समस्याएं हैं। इन

‘तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू

सुखन में ढलते हैं’, जौन एलिया ने कहा। उन्होंने रंग-ओ-खुशबू को शायरी के पैकर में ढाला, जिया और बरता। छोटी-छोटी पंक्तियों में बड़ी बातें कहने पर इसे शायर का जन्म 14 दिसंबर, 1931 को अमरोलाम में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद जौन असगर एलिया था। वे बेजोड़ शायर तो थे ही, गद्य पर भी उनको मलका हासिल था। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू भाषाओं पर जबर्दस्त पकड़ थी। जौश मलीहावदी और कमाल अमरोही के बारे में कहा जाता है कि उर्दू भाषा शब्द उनके सामने दस्तबस्ता खड़े हो जाते। जहां जिसकी जरूरत हुई, वहीं उस शब्द को रख दिया। लेकिन जौन एलिया भी हैं, जो लफ्जों को हुक्म देते और लफज कतार बांध कर, संवेदना की उंगली थामे, दर्द समेटे खड़े हो जाते। जादुई शायरी की इबारतें कागज और दिलो-दिमाग पर दर्ज हो जातीं। हर कोई उनकी शायरी के जादू में बंध जाता।

जौन ने महरूमियों को गले लगाया, बीमारी से लुफ्तअंदोज हुए। आत्मपीड़ा से लज्जत हासिल किया। जीवन की सच्चाई बयान करने वाले इस शायर ने खुद को सिगरेट की धुंध में भटकया। अंत

कब तक प्याज

राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज सौ से एक सौ चालीस रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मरुई में तो यह एक सौ अस्सी रुपए बिका। इसका कोई दो गंभीर कारण होगा। भारत में चाहे आप शाकाहारी खाना देख लें या मांसाहारी, दोनों में प्याज का खूब इस्तेमाल होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति एक हजार व्यक्ति पर नौ सौ अठार लोग प्याज खाते हैं।

ऐसे में जब भी प्याज महंगा होता है तो यह सुर्खियों में आ जाता है। बारिश के अलावा कम बुआई खराब फसल और कम उत्पादन और जमाखोरी भी प्याज को महंगा करने के अन्य बुनियादी कारण हैं। सन 2018 के बजट के समय प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता जताई थी कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम स्थिर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्याज के थोक व्यापारियों के मुताबिक कई जमाखोर प्याज सस्ता होने के बावजूद उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं और प्रशासन की ओर से जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालत यह है कि अब प्याज के इतना महंगा होने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर प्याज की माला पहन कर प्रदर्शन किया जा रहे हैं तो कहीं प्याज को भगवान मान कर उनकी पूजा की जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी हंगामा मचा हुआ है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसदों ने सरकार की तीखी आलोचना की। संसद के भीतर वह क्षण वाकई हास्यास्पद था जब चित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह ऐसे परिवार से आती हैं, जहां प्याज और लहसुन का मतलब ही नहीं है। फिलहाल प्याज के भाव में नरमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कीमतों में दिनोंदिन इजाफा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर बाजार में प्याज की कीमत दो

वैश्विक अशांति और जल

समस्याओं और चिंताओं में तीसरे विश्व युद्ध के बीच मौजूद हैं। ज्यादातर प्रचार यही है कि इस अंतरराष्ट्रीय उजाड़ का कारण आतंकवाद, सांप्रदायिक विभेद, सीमा-विवाद अथवा आर्थिक तनातनी है। किंतु सच यह नहीं है। सच यह है कि बढ़ती हवस, बढ़ता उपभोग, घटते प्राकृतिक संसाधन और दूसरे के संसाधन पर कब्जे की नीयत ने ये हालात पैदा किए हैं। इन संसाधनों में पानी सबसे प्रमुख है। यकीन न हो तो दुनिया के मानचित्र पर निगाह डालिए। आज तुर्की-सीरिया-इराक विवाद ने शिया-सुन्नी और आतंकवादी त्रासदी का रूप भले ही ले लिया हो, किंतु वास्तविकता यही है कि विवाद की शुरुआत इफ्रेटिस नदी के पानी को लेकर ही हुई थी। इफ्रेटिस नदी, तुर्की से निकल कर सीरिया होते हुए इराक तक जाती है। तुर्की का दावा है कि इस नदी में आने वाले कुल पानी में साढ़े अट्ठारसी प्रतिशत योगदान तो अकेले उसका ही है, फिर भी वह तो मात्र तियालीस प्रतिशत पानी ही मांग रहा है। दूसरा पक्ष देखिए। इफ्रेटिस के प्रवाह में सीरिया का योगदान 11.3 प्रतिशत और इराक का शून्य है, जबकि पानी की कमी वाले देश होने के कारण सीरिया, इफ्रेटिस के पानी में बाईस प्रतिशत और इराक तियालीस प्रतिशत हिस्सेदारी चाहता है। वस्तुस्थिति यह है कि तुर्की ने मूल नदी जल बंटवारा संधि (1987) का उल्लंघन करते हुए 15 अप्रैल, 2014 के बाद से इफ्रेटिस नदी के प्रवाह में कटौती करनी शुरु की और अपनी दादागीरी जारी रखते हुए 16 मई, 2014 को सीरिया और इराक के हिस्से का पानी छोड़ना पूरी तरह बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, नदी किनारे की खेती योग्य भूमि रेगिस्तान में तब्दील होती गई। सीरिया दुनिया में सबसे पुरानी खेती का देश है। नदी जल विवाद ने ऐसे देश के एक बड़े भू-भाग में खेती कार्य को दुष्कर बना दिया। इससे करीब बीस लाख की आबादी उजड़ी। उजड़ने वाले बगदाद गए, लेबाना गए, फिर ग्रीस, तुर्की से होते हुए जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और यूरोप के देशों तक पहुंचे। आज सीरिया में पानी का संकट इतना गहरा है कि सीरिया की करीब सत्तर प्रतिशत आबादी पीने के पानी की कमी से जूझ रही है। जब पीने को पानी ही पर्याप्त नहीं तो भूख का इंतजाम कहाँ से हो ?

यदि हम इफ्रेटिस नदी में 17.3 अरब क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता आंकड़े देखें तो समझ में आता है कि संबंधित तीनों देशों में पानी की मांग ज्यादा है और इफ्रेटिस नदी में पानी कम है। इसलिए मांग-जहरीला है। इसलिए ज्यादातर लोग किडनी में पथरी जैसी बीमारियों के शिकार हैं। फिलस्तीनियों के पास जमीनें हैं, लेकिन वे इतनी सूखी हैं कि वे उनमें कम पानी की फसलें भी नहीं उगा सकते। यही वजह है कि एक आम फिलस्तीनी, एक दुबई खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जब किसी न किसी इजरायली और फिलस्तीनी के बीच पानी को लेकर मारपीट न होती हो।

सीरिया, तुर्की, इराक, फिलस्तीन, इजरायल के ये टकराव तो नजीर मात्र हैं। मध्य एशिया और अफ्रीका के करीब चालीस देशों में कायम सामुदायिक अस्थिरता का मूल कारण पानी ही है। जॉर्डन, केन्या, यूथोपिया, सोमालिया, सूडान, ब्राजील सब जगह एक जैसे हालात हैं। समय बीतने के साथ-साथ यह

एक किताब के बराबर थे

आखिरकार निर्णय लिया गया कि इन तीन सौ पानों का सार तैयार

रही, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर उनकी महरूमी रही। महिलाएं उनकी इज्जत करती थीं, उनसे मुहब्बत नहीं करती थीं। यही अलमिया मजाज का भी था। मजाज की जीवनी ‘शोरिशे दौरा’ में हमीदा सलीम ने लिखा है कि महिलाएं मजाज की इज्जत करती थीं, उनकी शायरी पर आहें भरतीं, लेकिन उनसे मुहब्बत नहीं करती थीं। फिर भी, मजाज हों या कि जौन, दोनों ने प्रेम की आस में जिंदगी गुजार दी। जौन ने कहा- ‘उनकी उम्मीद नाज का/ हमसे ये मान था/ कि आप उम्र गुजार दीजिए/ उम्र गुजार दी गई।’

वरस, हिन्न-ए-फिराक यानी संयोग और विरह को उन्होंने कुछ इस अंदाज में पेश किया कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने दुनिया को गजल के एक नए लव-ओ-लहजे और शिल्प से परिचित कराया। जौन

एक किताब के बराबर थे
आखिरकार निर्णय लिया गया कि इन तीन सौ पानों का सार तैयार किया जाए। यही सार उनकी किताब ‘शायद’ में शामिल है। यह भूमिका भाषा, गद्य, कविता और दर्शन का बेजोड़ नमूना है। इसमें उन्होंने न सिर्फ कविता और जीवन दर्शन, बल्कि गणित, मनोविज्ञान, कॉस्मोलॉजी, समाजशास्त्र, धर्म के आपसी रिश्तों पर भी रोशनी डाली है। इस भूमिका में उन्होंने अपने निजी जीवन के ऐसे पहलुओं को भी उजागर किया है, जिसका हौसला उर्दू के बहुत कम साहित्यकारों और कवियों के पास है। ऐसा हौसला उनके अलावा साकी फारूकी ने अपने आत्मकथ्य ‘आप बीती पाप बीती’ में दिखाया है। जौन के अन्य काव्य संग्रह ‘गुमान’, ‘गोया’, ‘लेकिन’ और ‘यानी’ हैं। वे सारे संग्रह उनकी मृत्यु के बाद संकलित किए गए।

गािलब ने कहा है- ‘न गुल-ए-नमाा हूं न पर्दा-ए-साज/ मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज।’ यही शिकस्त

‘दुनिया मेरे आगे

‘पानीपत’ को लेकर राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक विरोध किया जा रहा है। सभी अपने जाति और धर्म से जुड़े किरदारों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। सिनेमा को मनोरंजक बनाने के लिए यथार्थ में थोड़ा-बहुत फेरबदल करने की छूट फिल्मकारों को मिल सकती है। लेकिन कई दफा ऐसे विरोध के कारण फर्लाप होने वाली फिल्म् भी हिट हो जाती है। फिल्मकारों को काम करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इतिहास के मामले में ज्यादा तोड़-मरोड़ की जाएगी तो कुछ सवाल उठ सकते हैं।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर***

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हैं। लिहाजा यह सवाल स्वाभाविक है कि इस बार प्याज के आंसू किसरे रोने पड़ेंगे।

- अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश***

यथार्थ और पर्दा

फिल्में चाहे धार्मिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक हों, सभी में थोड़ा मसला और हास्य भरा जाता है, ताकि दर्शक ऊबे नहीं। इधर इतिहास से जुड़ी फिल्मों को लेकर हमारा देश काफी संवेदनशील हो गया है। एक हजार साल पहले क्या हुआ था, उसे लेकर हम आज मरने-मारने को तैयार रहते हैं। 2008 में ‘जोधा अकबर’ से लेकर पिछले साल ‘पद्मावत’ को लेकर काफी हल्लागुल्ला हुआ। अब आशुतोष गोवारिकर की फिल्म



जहरीला है। इसलिए ज्यादातर लोग किडनी में पथरी जैसी बीमारियों के शिकार हैं। फिलस्तीनियों के पास जमीनें हैं, लेकिन वे इतनी सूखी हैं कि वे उनमें कम पानी की फसलें भी नहीं उगा सकते। यही वजह है कि एक आम फिलस्तीनी, एक दुबई खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जब किसी न किसी इजरायली और फिलस्तीनी के बीच पानी को लेकर मारपीट न होती हो।

सीरिया, तुर्की, इराक, फिलस्तीन, इजरायल के ये टकराव तो नजीर मात्र हैं। मध्य एशिया और अफ्रीका के करीब चालीस देशों में कायम सामुदायिक अस्थिरता का मूल कारण पानी ही है। जॉर्डन, केन्या, यूथोपिया, सोमालिया, सूडान, ब्राजील सब जगह एक जैसे हालात हैं। समय बीतने के साथ-साथ यह

बैरागी शायर

सुखन में ढलते हैं’, जौन एलिया ने कहा। उन्होंने रंग-ओ-खुशबू को शायरी के पैकर में ढाला, जिया और बरता। छोटी-छोटी पंक्तियों में बड़ी बातें कहने पर इसे शायर का जन्म 14 दिसंबर, 1931 को अमरोलाम में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद जौन असगर एलिया था। वे बेजोड़ शायर तो थे ही, गद्य पर भी उनको मलका हासिल था। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू भाषाओं पर जबर्दस्त पकड़ थी। जौश मलीहावदी और कमाल अमरोही के बारे में कहा जाता है कि उर्दू भाषा शब्द उनके सामने दस्तबस्ता खड़े हो जाते। जहां जिसकी जरूरत हुई, वहीं उस शब्द को रख दिया। लेकिन जौन एलिया भी हैं, जो लफ्जों को हुक्म देते और लफज कतार बांध कर, संवेदना की उंगली थामे, दर्द समेटे खड़े हो जाते। जादुई शायरी की इबारतें कागज और दिलो-दिमाग पर दर्ज हो जातीं। हर कोई उनकी शायरी के जादू में बंध जाता।

ऐसे में जब भी प्याज महंगा होता है तो यह सुर्खियों में आ जाता है। बारिश के अलावा कम बुआई खराब फसल और कम उत्पादन और जमाखोरी भी प्याज को महंगा करने के अन्य बुनियादी कारण हैं। सन 2018 के बजट के समय प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता जताई थी कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम स्थिर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्याज के थोक व्यापारियों के मुताबिक कई जमाखोर प्याज सस्ता होने के बावजूद उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं और प्रशासन की ओर से जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालत यह है कि अब प्याज के इतना महंगा होने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर प्याज की माला पहन कर प्रदर्शन किया जा रहे हैं तो कहीं प्याज को भगवान मान कर उनकी पूजा की जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी हंगामा मचा हुआ है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसदों ने सरकार की तीखी आलोचना की। संसद के भीतर वह क्षण वाकई हास्यास्पद था जब चित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह ऐसे परिवार से आती हैं, जहां प्याज और लहसुन का मतलब ही नहीं है। फिलहाल प्याज के भाव में नरमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कीमतों में दिनोंदिन इजाफा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर बाजार में प्याज की कीमत दो

सौ रुपए प्रतिकिलो के पार निकल गई है। इसकी वजह प्याज की कम उपलब्धता है। व्यापारियों का यह तक कहना है कि इस महीने के अंत तक प्याज की कीमतें ऊंची बने रहने के आसार हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम मरने वामों पर आयात के लिए मजबूर हुए हैं। ध्यान रहे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मोदी सरकार के वायदे और लक्ष्य में बागवानी फसलों की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बेशक बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि प्याज की कीमतों ने कई सरकारी दावे ध्वस्त कर डाले

समस्या और गंभीर होती जा रही है। जैसे-जैसे दूसरे देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है। सत्ता में बने रहने की राजनीतिक चालें, जस संकट से उपजे इस संकट को वर्ग और सांप्रदायिक विभेद और राष्ट्रवादी नारों के रंग भरकर पेश कर रही हैं। ये चालें दुनिया को हिंसा और युद्ध के जिस रंगभंग की ओर ले जा रही हैं, क्या यह पानी की खातिर विश्व युद्ध का कुरुक्षेत्र नहीं है?

सवाल है कि क्या भारत इससे अछूता है? इस साल मार्च में दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में पानी के झगड़े में एक की हत्या कर दी गई थी। पानी की आपूर्ति में कमी और बिल में बढ़ोत्तरी के विरोध जयपुरवासी सड़क पर उतरे। शिमलावासियों के नलों में तीसरे दिन आते पानी का आक्रोश, स्वयं हिमाचल के महाहिम राज्यपाल के मन में दिखा। उत्तराखंड के बानवे में से इकहतर नगरों-कस्बों में मानक से बहुत कम और खराब पानी मिला।

पानी से जुड़ी कई समस्याएं भारत के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण बनती जा रही हैं। सतलुज नदी बंटवारे के कारण हरियाणा-पंजाब के बीच तलवारें खिंची रहती हैं। कावेरी जल विवाद का आक्रोश हमने बीते मार्च-अप्रैल के दौरान संसद में भी देखा और सड़कों पर भी। मानसरोवर स्थित मूल स्रोत से निकलने वाली सिंधु नदी के लड़ाख क्षेत्र में कब्जे की चीनी साजिशों से हम वाकिफ हैं ही। भारत आने वाले तिब्बती प्रवाहों में चीन द्वारा परमाणु कचरा डालने और बांध बना कर पानी रोकने की करतूतें पुरानी हैं। जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद हैं। नेपाल मूल की नदियों में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से भारत में होने वाली तबाही को लेकर हम चिंतित रहते ही हैं।

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी। कम पानी और वर्षा आधारित खेती-बागवानी को अपनाना चाहिए। जितना पानी कुदरत से ले, उसे वैसा ही उतना पानी संचित करके लौटाना चाहिए। जितना पानी बरसता है, उसे संचित करके हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे जल संकट का समाधान भी हमारे प्रबंधन में ही है।

काफ़का पर ईमान लाए। उन्हें शुरू से ही किताबों का शौक था, इस्क भी, जिसकी वजह से वे जिंदगी और मुहब्बत दोनों में कामयाब न हो सके। वे कहते हैं- ‘इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर/ उनमें इक रम्य है/ जिस रम्य का मारा हुआ जहन/ मुब्त्दा-ए-इशरत अंजाम नहीं पा सकता/ जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।’ उनका कहना था कि धर्म के ठेकेदारों के पास दौलत, ताकत और हुक्मत आ जाने पर चारों तरफ खोफ का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। खौफ, नफरत और सांप्रदायिकता की जो फलत पाकिस्तान कट चुका है। उसकी फसल अब भारत में भी तैयार खड़ी है। उनका यह शेर कितना प्रार्संगिक है। ‘नमाज-ए-खौफ के दिन है। कि इन दिनों यारो/ कालंदरों पे फकीहों का खौफ तारी है।’

जौन का मतलब होता है वजा, आभा या भेष। एलिया फनकारों, कलाकारों और मनीषियों की रहस्यमयी बस्ती का नाम है। उनका भेष सबसे निराला था। अपने बड़े-बड़े बालों को झटक कर जानू यानी घुटने पर हाथ टोंक कर बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में कविता पाठ करते।

चौजे महंगी हैं। प्राचीन वृक्षों को, जो बीमार, अंदर से पोले या गिरने की कगार पर हो, उसका उपचार भी किया जाना चाहिए। पर्यावरण के हिसाब से यह गंभीर चिंता की बात है कि अधिक जंगल काटने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा। यह सर्वविदित है कि वृक्षों से ताप का नियंत्रण होता है और वायुमंडल की विषाक्तता भी कम होती है। जितने अधिक वृक्ष होंगे, वातावरण उतना ही शुद्ध और स्वच्छ होगा। गरमी में ईसान, पशु, पक्षी और वाहनों को छांव की तलाश रहती है, वृक्षों के होने से जीवन सुखद होता है। भविष्य मे हरित क्रांति को विलुप्त होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण के पुनीत कार्य और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में भागीदारी निभाए।

- संजय वाम्पूट्टी, मनावर, धार***

अपारदर्शी व्यवस्था

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआई और चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है कि चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता रखना राष्ट्रहित में नहीं है। यानी इस अपारदर्शी व्यवस्था के दूरगामी परिणाम घातक होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट कंपनियां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को पनवाने के फीसद धन को चंदे के रूप में देती हैं। इसकी जानकारी सरकार को भले ही हो, लेकिन आम जनता को नहीं है। आखिर हर क्षेत्र में पारदर्शिता का नाम जपने वाली सरकार की चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता रखने की मंशा क्या है? चुनाव के बाद कंपनियों के कोई खास फायदे के लिए तो कहीं यह राजनीति-कॉरपोरेट गठजोड़ नहीं है? वाकई चुनावी बॉन्ड जैसी सुविधा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगी और सरकारें भी ‘राष्ट्रहित’ के बजाय ‘कंपनी हित’ को तवज्जी देंगी। चुनाव आयोग को सशक्त बना कर और राजनीतिक दलों को आरटीआइ कानून के दायरे में लाया जाए, ताकि इस गठजोड़ को नाकाम किया जा सके।

- कपिल एम वडियार, पाली, राजस्थान***

सियासत की बीमारी संकामक हो गई है। दायरा सियासी दलों से बढ़कर साधू-संतों और खेल व खिलाड़ियों तक भी पहुंच चुका है। धर्म नगरी हरिद्वार में 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर भी संत अंधी से एक-दूसरे की टांग खींचने में जुट गए हैं। अखाड़ों की छावनियों के लिए जमीन और खासी रकम की मांग कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने अपना प्रभुत्व दिखाना चाहा है। सरकार को दबाव में लेने के मकसद से कुंभ के कामकाज की गति सुस्त होने का आरोप लगाया है। जबकि त्रिवेन्द्र सिंह रावत इस मामले में चुक करते नहीं दिख रहे। गिरि ठहरे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के चहेते। संधी खेमे के साधू-संतों से पटती नहीं। तभी तो सूबे की भाजपा सरकार भी उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही। वैरागी अखाड़े के महंत बाबा हट योगी उन पर खुलेआम शब्दबाण चला रहे हैं। उनकी अखाड़ा परिषद को ही फर्जी बता दिया। हट योगी तो सरकार से उलट मांग कर रहे हैं कि वह उन अखाड़ों को छावनी के लिए कतई जमीन न दे जिन्होंने अपनी छावनी में बहुमंजिला इमारतें बना रखी हैं। रही नरेंद्र गिरि की बात तो वे सरकार के शाइन बोर्ड बनाने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। हट योगी इसके मुखर समर्थक बन कर उभरे हैं।

राजपाट

बढ़ती कलह

सत्ता की हनक अलग ही होती है। सत्ता से पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती है। नई सियासी रवायत तो यह भी कहती है कि मूल ध्येय सेवा नहीं सत्ता हथियाना होना चाहिए। नीति सिद्धांत बेमानी है। येन केन प्रकारेण या कहें कि साम-दाम-दंड-भेद कोई भी तरीका अपनाया जाए, बस सत्ता मिलनी चाहिए। गोवा और उत्तर-पूर्व के राज्य ही नहीं कर्नाटक की मिसाल पहले से थी। रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में भी असफल कोशिश हुई थी। पर तीन दलों का मोर्चा भारी पड़ गया। बहरहाल सत्ता से दूरी होते ही महाराष्ट्र भाजपा में अंतरकलह सतह पर दिखने लगी है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पार्टी के पिछड़े और मराठा नेता लामबंद हो रहे हैं। एकनाथ खडसे और पंकजा मुंडे के सुर एकदम बागी हैं। सुगुणगाहट और भी कई स्तर पर जारी है। गुरुवार को बीड में पंकजा ने अपने दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर रेली कर खूब भड़ास निकाली। एकनाथ खडसे तो थे ही पार्टी के सूबेदार चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी हेरान करने वाली थी। पंकजा और खडसे ने फडणवीस का नाम लिए बिना खुद की उपेक्षा का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा। पंकजा ने फरमाया कि विधानसभा चुनाव के वक्त विनोद तावड़े और एकनाथ खडसे जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट यह कह कर काट दिए गए कि आलाकमान ऐसा चाहता है। पर मेरी जानकारी है कि आलाकमान के बजाए सूबे के प्रभावशाली नेताओं ने यह खेल किया। संकेत फडणवीस की तरफ था। खडसे ने जहां पार्टी छोड़ने का संकेत दिया वहीं पंकजा ने ऐसा करने से इनकार किया। अलबत्ता चेतावनी के अंदाज में कहा कि वे साफगोई की राह नहीं छोड़ेंगी। खुद पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं पर पार्टी उनके बारे में निर्णय को स्वतंत्र है। पंकजा ने कहा कि वे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं गई थीं। पार्टी सीट पर अपनी हार के लिए भी उन्होंने फडणवीस को दोष दिया। साथ ही संकेत दिया कि वे अगले साल जनवरी में लोगों के बीच जाएंगी। रेली में खुद पंकजा ने लोगों से कहा कि वे चंद्रकांत पाटिल को हट न करें। खडसे ने फडणवीस पर हमला बोलते हुए यह भी कह दिया कि गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा देवेंद्र फडणवीस ने नहीं लगने दी। उन्होंने फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि वे पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ तो बोल ही सकते हैं जिन्होंने मीठी बातें करके अपनों की पीठ में ही छुरा भोंक दिया। मैंने न चोरी की और न भ्रष्टाचार। फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया? खडसे ने अजित पवार से समर्थन लेने के लिए भी फडणवीस पर हमला बोला था। वे एनसीपी और शिवसेना नेताओं से भी मिल रहे हैं।

वक्त का फेर

टोटे में लड़ाई होती ही है, इस पुरानी कहावत को हम राजस्थान भाजपा में खरा साबित होते देख सकते हैं। साल भर पहले सूबे की सत्ता से बेदखल होते ही भाजपा में गुटबाजी सतह पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके विरोधियों के बीच ताकत दिखाने का खेल शुरू हो गया है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थीं और फिर पद से हट गई थीं तो सूबे की सियासत से दूरी बना ली थी। वैसा ही इस बार भी दिख रहा है। चूंकि सत्ता में रहने का स्वभाव है सो विपक्ष की सियासत उन्हें रास आती भी नहीं। तभी तो भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ चाहे जो कार्यक्रम करे, वसुंधरा उससे दूर ही नजर आती हैं। पार्टी की बैठकों में शामिल होना भी वे अपनी तौहीन समझती हैं। ऊपर से आलाकमान ने उनके धुरविरोधी और आरएसएस के प्रति निष्ठावान सतीश पुनिया को पार्टी का सूबेदार बना कर वसुंधरा को और चिढ़ा दिया। सो, वे तो संगठन से दूर हैं ही, उनकी सरकार में सत्ता की मलाई खाने वाले दूसरे कई नेता भी संगठन के काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। सूबे में इन दिनों भाजपा में मंडल और जिला स्तर के संगठन चुनाव चल रहे हैं। पर वसुंधरा को कोई रुचि नहीं। निचले स्तर पर संगठन में अब संधी खेमे का दबदबा है। तो भी वसुंधरा खेमे के नेता दावा कर रहे हैं कि चार साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वसुंधरा राजे की कद्र करनी ही होगी। यानी फिर चलेगी तो उन्हीं की। हालांकि, वसुंधरा खेमा भ्रम का शिकार लगता है। पार्टी की आबेहवा बदल चुकी है। आलाकमान अब वसुंधरा जैसे नेताओं से छुटकारा पाने की जुगत में है। तभी तो नया नेतृत्व उभारा जा रहा है। कोटा के ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना महज संयोग नहीं है। केंद्र में मंत्री भी नए हैं। वसुंधरा के बेटे को संसद में वरिष्ठता के बावजूद राज्यमंत्री तक का पद नहीं मिल पाया। नए सूबेदार सतीश पुनिया अपने पांव जमा रहे हैं। पिछले दिनों विदेश यात्रा से वापस आए तो जवपू में ऐसा भव्य स्वागत हुआ मानो वे पार्टी अध्यक्ष न होकर मुख्यमंत्री बनने वाले हों। नारे भी लगे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, सतीश पुनिया जैसा हो। वसुंधरा खेमे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि आलाकमान की सहमति के बिना इस तरह के नारे कौन लगा सकता है।

बम बम भाजपा

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से तो पारित हो गया पर उत्तर-पूर्व के राज्यों में इसकी जैसी प्रतिक्रिया हुई है, वह भाजपा के लिए खतरों की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों में अपना प्रभाव बेशक बढ़ाया। वहां अलगवावाद की सुलगीत आग भी काफी ठंडी पड़ गई थी। पर इस विधेयक के बाद तो हालत इस कदर बेकाबू हो गए कि कर्पूर्व भी लगाना पड़ा और सेना को भी बुलाना पड़ गया। पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा को इस प्रतिक्रिया का अंदाज न रहा हो। असम के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि इस विधेयक का विरोध होगा। पर बड़े फायदे के लिए कुछ जोखिम लेना ही पड़ता है। उत्तर-पूर्व में जनजातियों के विरोध से जितना ज्यादा नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा भाजपा को शेष भारत में मुसलमान विरोधी धुवीकरण बढ़ने से होने का अनुमान है। विपक्ष चौख कर कहता रहा कि मजहब के आधार पर भेदभाव की संविधान का अनुच्छेद 14 इजाजत नहीं देता। यह भी कि बहुमत के दम पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। पर तीन तलाक व धारा 370 के बाद नागरिकता कानून के एजेंडे को भाजपा ने लागू कर ही दिया। राममंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी उसके मनमाफिक ही आया है। ऐसे में अगला कदम समान नागरिक संहिता का होना स्वाभाविक है। विपक्ष के पास अब कानूनी जंग के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। पर रफाल व अयोध्या विवाद की अदालती जंग हार चुका विपक्ष इस मुद्दे पर भी अनुकूल अदालती फैसले की उम्मीद आत्मविश्वास के साथ तो नहीं कर सकता।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

विरोध कर रहे लोगों के साथ? आज के दौर में जब नागरिक स्मार्ट फोन के डाटा में तब्दील हो गए हैं और इतिहास वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है तो गांधी के सरोकारों को कैसे समझाया जाएगा। बीसवीं सदी में विश्वविद्यालयों से निकले छात्र नेता जो इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ थे इक्कीसवीं सदी में वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं हैं। सत्ता के अहंकार और विखंडित विपक्ष में फंसी जनता पर बेबाक बोल।



मुकेश भारद्वाज

बोध और विरोध

असम विरोध में जल रहा है तो दिल्ली के मजनु का टीला स्थित पाकिस्तानी शरणार्थी कॉलोनी में जन्मी बच्ची का नाम 'नागरिकता' रखा गया है। देश कागज पर खींचा नक्शा नहीं बल्कि असम से लेकर मजनु का टीला तक की जटिलता है। इस साल जब हम महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मना चुके हैं तो विभाजन से जुड़े इतिहास के पन्ने अपनी-अपनी राजनीति की टिप्पणियों के साथ पलटे जा रहे हैं। आज गांधी होते तो किसके साथ होते? शरणार्थी शिविर में पैदा हुई नवजात 'नागरिकता' के साथ या असम में

मेरी हस्ती से हर शख्स बेजार क्यों है
हर हाथ में मेरे लिए तलवार क्यों है
मैं तो खुद ही तैयार हूँ महफिल से विदा होने को
फिर यह रोज-रोज की तकरार क्यों है।
ह सवाल जनता की तरफ से है जो जनतंत्र की बुनियादी शर्त है। पर संसद का सीधा प्रसारण बता रहा है कि जनता से लोकतंत्र के मंदिर (आधुनिक बोध के हिसाब से संसद के लिए मंदिर शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए) में कमजोरों के प्रति अहंकार की भाव-भंगिमा है, वह जरूर नया है। संसद में वित्त मंत्री का उच्चारण और भाव-भंगिमा उन लोगों पर लानत भेज रहा था जो लहसुन-प्याज खाते हैं। जैसे लहसुन-प्याज न खाने वाले कितनी उच्च कोटि के हो गए और खाने वाले एकदम अधम। वित्त मंत्री का अहंकार बताता है कि संसद में बैठे लोगों और जनता के बीच दूरी कितनी बढ़ गई है। कांग्रेस के 'संभ्रंत' नेता शशि थरुन ने जब हवाई जहाज की सामान्य श्रेणी को मवेशी वर्ग (कैल्ट क्लास) कहा था तो भी हंगामा मचा था। मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद जब बार-बार कपड़े बदलने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटील पर सवाल उठाया गया तो उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब तो दिखावे के नाम पर भी 'लोकतांत्रिक दिखावा' बंद कर दिया गया है।

मंदी का कारण यह नई पीढ़ी है जो गाड़ियां खरीदने के बजाए ओला और उबर से चलती है। सिनेमा हॉल में टिकट बिक रहे हैं, फिल्में सौ करोड़ का कारोबार कर रही हैं तो मंदी कहाँ है। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी है तो फिर सड़कों पर इतना जाम क्यों लग रहा है। भारत में अभी तक ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है जिससे पता चले कि प्रदूषण के कारण मौतें हो रही हैं। ऐसे बयान देते वक्त माननीय सांसदों को देह से जो अहंकार फूटता दिखाता है, उससे यही लगता है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होता तो कुछ भ्रम बचा रहता, नागरिकता के प्रमाणपत्र पर गर्व तो महसूस किया जा सकता था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द राहत मिलेगी, यह विपक्ष की साजिश है, अंतरराष्ट्रीय कीमते बढ़ रही हैं जैसे दिल्लीसा देनेवाली भाषा की भी अब जरूरत महसूस नहीं की जा रही। सारी पदेंदारी खत्म है। हमारा करने का मन है इसलिए ऐसा किया, हम यही करने के लिए आए हैं इसलिए ऐसा किया। रामराज्य में भी अपराध शून्य नहीं हो सकता। सरकार सभी को नौकरियों नहीं दे सकती है। लोग बच्चे पैदा कर सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। अगस्त में बच्चे मरते ही हैं जैसे चाक्य बोल कर नेता उसे संदर्भ सहित सही साबित करने में जुट जाते हैं और विपक्ष वैसी जिंदा कौम नहीं रह गई है कि पांच साल के पहले कुछ सोचे भी।

जनता तो अब स्मार्टफोन में तब्दील हो रही है, जहां नागरिकता बोध का कोई अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) ही नहीं। इतिहास किताबों से निकल



असम में विरोध प्रदर्शन करते लोग।



दिल्ली के शरणार्थी शिविर में जश्न मनाते लोग।

कर वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है। सत्ता की कूरता मीम है और जनता की जंग चुटकुला। एक वर्ग को निःशुल्क शिक्षा के लिए हड़ताल करते जेएनयू के विद्यार्थी दुश्मन लगते हैं और वह अपने आयकर का हिसाब मांगने लगता है। वह अब किसी भी सरकार से सवाल नहीं करता। सत्ता के लिए इससे सुखद स्थिति क्या हो कि जनता ही जनता से लड़े और वहीं एक-दूसरे से जवाब मांगे।

उदारिकरण की अर्थव्यवस्था की नाकामी का कोई हल नहीं दिख रहा था तो दुनिया भर में इसका ठीकरा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही फोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता शब्दों को खारिज किया गया। आधार संस्था की बुनियादी जरूरतों के वास्ते अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान महाधिवक्ता दलील देते हैं कि नागरिकों के शरीर पर राज्य का अधिकार होता है। लोकतंत्र सत्ता के कर्तव्य और जनता के अधिकारों के लिए बनाया गया लेकिन अब इसे उलटा अर्थ दिया जा रहा है। अब सत्ता के पास अधिकार और अहंकार है और जनता के पास सिर्फ कर्तव्य।

सत्ता के अहंकार को दूर करने के लिए फिलहाल तो दूर-दूर भी विकल्प नहीं दिख रहा है। जोड़-तोड़ की बात छोड़ दें तो कर्नाटक के उपचुनाव में वे भी भाजपा सांसद चुन कर आ गए जो दलबदल कानून के तहत सदन से बेदखल थे। जद (सेकु) और कांग्रेस को नकारते हुए जनता ने फिर उन्हें सदन में पहुंचा दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त जो राजनीतिक विश्लेषण हुए थे उपचुनावों के बाद वे सिर्फ बगलें ही झांक सकते हैं। जब राजनीतिक टिप्पणियों की उम्र इतनी छोटी हो जाए, सत्ता और जनता विपरीत व्यवहार करे तो फिलहाल थोड़ी देर रुक कर सोचने-समझने की कोशिश करनी चाहिए।

सत्ता और जनता दोनों संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं। राममनोहर लोहिया की मशहूर उक्ति है कि अगर सड़कें खांमोश हो जाएं तो संसद आवाज हो जाएगी। लेकिन अभी तो सड़क पर जनता है, पुलिस की पानी की बौछार और हिरासत में लेने का दौर है। सड़क

पर खड़ी इस जनता का संसद तक असर होगा? मौजूदा सरकार में जब वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों की सूची देखें तो इनमें से ज्यादातर चेहरों का करिश्मा आपातकाल के दौरान उभरा था। 1975 के विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कांग्रेस के खिलाफ विकल्प बनकर संसद पहुंचे और वही लोग आज सड़क पर बैठे शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को अलोकतांत्रिक बता रहे। सूनी सड़क से आवाज संसद की आशंका जताने वाले के कई शिष्य आज नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में खड़े हैं।

देश महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मना चुका है और विभाजन के इतिहास के पन्ने अपनी-अपनी सुविधानुसार और अपने-अपने फुटनोट के साथ सामने लाए जा रहे हैं। विभाजन के इतिहास में दर्ज है महात्मा गांधी और नोआखली। गांधी नोआखली में अकेले घूम रहे थे क्योंकि एक बड़ी कौम को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। आजादी के बाद से न जाने कितने नोआखली बने लेकिन वहां जनता की सुरक्षा के लिए अकेले घूमने वाले गांधी नहीं मिले। नोआखली की न जाने कितनी प्रतिकृति (क्लोन) तैयार हुई पर गांधी जो गए तो फिर किसी तरह नहीं बने। आज गांधी होते तो किधर जाते? नागरिकता बिल के विरोध में जल रहे असम की तरफ या दिल्ली में अभावों की गडरी के साथ मजनु का टीला पर जश्न मनाते पाकिस्तान से आए उस हिंदू शरणार्थी की तरफ जिसने जन्म ली नवजात का नाम नागरिकता रखा है। देश कागज पर खींचा आसान नक्शा नहीं होता बल्कि मजनु का टीला से लेकर असम तक की जटिलता होता है। इस जटिलता का हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में गांधी के अलावा कोई हल नहीं है।

संसद, सड़क और जनता के रिश्ते में एक बार फिर से खारिज नागरिक ही है। बस इस नकारनामे पर दस्तखत करने वालों की कलम की स्याही बदल गई है। कागज और कलम के रिश्ते में स्याही का रंग आगे क्या रूप लेता है, उस पर आज इतनी जल्दी बोल कर कल खारिज होने का जोखिम कैसे लें।

इस विशेष पन्ने पर आपके डेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुकाम नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

नैतिकता की भी जरूरत

यौन हिंसा के मामले घर की चारदीवारी के अंदर भी होते हैं। लेकिन समाज में झूठी शान और बेइज्जती के डर से उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर ही रफा-दफा कर दिया जाता है, जिससे अपराधियों के होसले बुलंद हो जाते हैं। देश में बलात्कार के बढ़ते अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। अगर इन पर नकेल कसने के लिए अभी गंभीरता नहीं दिखाई गई या फिर इसके लिए प्रयास सरकार और समाज ने मिलजुलकर नहीं किए तो आने वाला समय इससे भी विकट हो सकता है। सख्त कानून के साथ-साथ जब तक लोगों में नैतिकता की भावना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा तब तक शायद ऐसी धिनीनी घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि अगर बच्चों को बचपन से ही नैतिकता का सबक पढ़ाया जाए तो हमारे समाज में बढ़ रहे गलत कामों पर लगाम लग सकती है। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं।

- राजेश कुमार चौहान।

हालात का पोस्टमार्टम

आर्थिक उदारीकरण के दौर में व्यस्ततम जीवन-शैली ने बच्चों के साथ हमारा संबंध सीमित कर दिया है। हम उन्हें परिपक्व सोच नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में भला महज कानून के सहारे अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं। किस-किस को और कहाँ-कहाँ मारेंगे हम, जब समाज की मानसिकता ही हमारी

अपनी कमजोरी के कारण बीमार होते जा रही है? कानून जो भी बने, जितना भी सख्त बने जरूरत है इस बात की है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सुधार संभव है।

-डॉ. हर्षवर्द्धन, शिक्षाविद, लोहानीपुर-कदमकुआं, पटना।

भरोसा न टूटे

वहां एक लड़की नहीं इंसानियत जल रही थी। सड़क से सदन तक इस कदर भरोसे टूटते रहे तो एक दिन शब्दकोश से भरोसे और यकीन जैसे लपज ही गायब हो जाएंगे। एक बार रुक कर सोचें तो सही कि अदालतें न रही तो भरोसा किस चौखट खड़ा मिलेगा। वक्त रहते वो सारे जतन करने होंगे जिस से किसी का भरोसा न टूटे। वरना इस मुक्त की तबाही रोक पाना यकीन मुश्किल हो जाएगा।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातु।

हल निकालना ही होगा

कमजोर पर मजबूत का वर्चस्व सदियों से चला आ रहा है। सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद लड़की को मार डालने की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति खोफनाक है। समाज और शासन की सभी संस्थाओं को अपनी कमियां खोज इसका हल निकालना ही होगा।

-पारस एफ खेमसरा, 205 तिरुपति विहार, मध्य प्रदेश।

सही नेतृत्व की जरूरत

सबसे पहला कदम संसद को बढ़ाना होगा कि न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने की ओर प्रयास किए जाएं। इसके बाद घर और समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए कि बच्चे देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। नागरिक बोध को बढ़ाकर ही हम हिंसक मानसिकता से पीछा छुड़ा सकते हैं।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

घटना कानून का इकबाल

सवाल कानूनी नीति का नहीं बल्कि नीयत का है क्योंकि कोई भी खास घटना के विरुद्ध आयोजित कैंडल मार्च की लौ समय की रफ्तार और संवेदनाओं की शून्यता में 'हो हुआ सो हुआ' के समझौते का सारथी बन जाता है। उम्मीद के होसले समाधान की पटकथा लिख सकेगा तभी तो किसी ने कहा है, 'आसमानों से बरसता है ये अंधेरा कैसा, अपनी पलकों पे लिए जश्न-ए-चिरागों चलिए'।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

भीड़ समाधान नहीं

'बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए' ये बयान तो निश्चित रूप से पाषाणकालीन बर्बर युग की पुनर्स्थापना करने का एक कुत्सित और घृणित कृत्य ही है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

कई अहम विधेयक पारित, राज्यसभा के सत्र को ऐतिहासिक बताया नायडू ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

संसद का 18 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों में कामकाज का फीसद सौ फीसद से अधिक रहा। सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक, एससी/एसटी आरक्षण को दस साल आगे बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में सभापति एम वैकेया नायडू ने अपने पारंपरिक भाषण में सत्र के दौरान हुए कामकाज पर संतोष जताते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर अपने पारंपरिक भाषण में कहा कि सभा की उत्पादकता 115

फीसद दर्ज की गई।

सत्र के दौरान नागरिकता (संशोधन) विधेयक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण को दस साल बढ़ाने संबंधी संविधान (126वां) संशोधन विधेयकों पर सदन में लंबी चर्चा हुई तथा विपक्ष एवं सत्तापक्ष के लोगों ने खुल कर अपने विचार रखे। इस दौरान ई सिगरेट पर रोक लगाने संबंधी विधेयक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र संबंधी विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों को चर्चा कर पारित किया गया।

साथ ही उच्च सदन में लंबे अंतराल के बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी थी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकें हुईं, जो 130 घंटे 45 मिनट चलीं। 2019-20 के लिए अनुदान की

अनुपूरक मांगों पर पांच घंटे और पांच मिनट चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पुनःस्थापित हुए और कुल मिला कर 14 विधेयक पारित हुए।

बिरला ने कहा कि 140 तारकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 प्रश्नों के जवाब दिए गए। इसके अलावा प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रतिदिन औसतन 58.37 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन कुल 364 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सभा की उत्पादकता 115 फीसद दर्ज की गई। राज्यसभा में सत्र के दौरान 108 घंटे 33 मिनट तक निर्धारित कामकाज होना था। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के चलते सदन के कामकाज में 11 घंटे 47 मिनट का नुकसान हुआ। किंतु सदस्यों ने 10 घंटे 52 मिनट अधिक काम कर सदन को उत्पादकता को 100 फीसद पर ला दिया।

सत्र के दौरान उच्च सदन में कुल 15 विधेयक पारित किए गए या विचार कर लौटाए गए। इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक शामिल है जो इस तरह के व्यक्तियों के हितों के लिए लाया गया अपनी तरह का पहला विधेयक है। सत्र के दौरान सदस्यों ने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा शून्यकाल में एवं विशेष उल्लेख के जरिए लोकमहत्त्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। यह सत्र प्रश्नकाल के लिहाज से भी 1971 के बाद पिछले 49 सालों में सबसे बेहतरीन रहा। इस दौरान कुल 255 मौखिक सवालों में से 171 के जवाब दिए गए जो कुल सवालों का 67 फीसद है। इस प्रकार सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.5 मौखिक सवालों के जवाब दिए गए। सभापति ने राज्यसभा के 250वें सत्र को ऐतिहासिक सत्र करार देते हुए कहा कि इसकी ‘गंभीरता एवं संक्षिप्तता’ महत्त्वपूर्ण रही।

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रह

जापान सरकार ने नई दिल्ली को साफ बता दिया कि बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आबे के लिए गुवाहाटी आना संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बैठक अगले साल होने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह आबे के दौरे की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन आयोगन स्थल का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, शिखर सम्मेलन के लिए गुवाहाटी में जोर शोर से तैयारियों की जा रही थीं। जापान सरकार की एक टीम ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया, जिसके बाद तोक्यो ने विदेश मंत्रालय को बताया कि मौजूदा परिस्थिति में आबे का दौरा नहीं हो सकता। जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जापान ने उन अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतियां भारत के विदेश मंत्रालय को भी सौंपी हैं।

कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंची भाजपा की महिला सांसद

नई दिल्ली/इंदौर, 13 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि झारखंड की चुनावी रैली में राहुल गांधी की ‘रेप इन इंडिया’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में भाजपा की महिला सांसदों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ ‘कठोरतम संचार कार्रवाई’ की मांग की।

ईरानी ने कहा कि भाजपा की महिला सांसद इतनी नाराज हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। उन्होंने चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, ‘हमने निर्वाचन आयोग से कहा कि यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक नेता ने राजनीतिक मजाक के लिए बलात्कार का इस्तेमाल किया है। पूरा देश इस संवैधानिक संस्था (चुनाव आयोग) की ओर देख रहा है

ताकि महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा जा सके और जो नेता बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।’ ईरानी ने कहा कि उन्होंने यह निर्वाचन आयोग पर छोड़ा है कि गांधी को क्या सजा दी जाए।

उन्होंने पूछा कि किसने राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक विचार देश की छवि को धूमिल करने का अधिकार दिया है? ईरानी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि वह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार न्याय करेगा। इस बीच, इंदौर के एक स्थानीय भाजपा नेता ने मुकेश राजावत शुक्रवार को यहां जिला अदालत में राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई। राजावत के वकील अमित सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने इस शिकायत को भीपाल की एक विशेष अदालत को भेज दिया जिसे सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

पेज 1 का बाकी
से संबंधित मामले के साथ संलग्न करते हुए कहा कि इन पर फरवरी, 2020 में सुनवाई होगी। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्मस (एडीआर) और कॉमन कॉज ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग की भविष्य के सभी चुनावों में आंकड़ों की विसंगतियों की जांच के लिए पुष्टा प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। एडीआर ने अपने विशेषज्ञों की टीम के शोध आंकड़ों की हवाला देते हुए कहा है कि 2019 में संपन्न हुए चुनावों में विभिन्न सीटों पर मतदाताओं की संख्या और मत फीसद और गिनती किए गए मतों की संख्या के बारे में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों मे गंभीर

विसंगतियां हैं। याचिका में दावा किया गया है कि उनके शोध के दौरान अनेक विसंगतियों का पता चला। याचिका में कहा गया है कि ये विसंगतियां एक मत से लेकर 1,01,323 मतों की हैं। जो कुल मतों का 10.49 फीसद है। याचिका के अनुसार छह सीटों पर मतों की विसंगतियां चुनाव में जीत के अंतर से ज्यादा थीं। याचिका में किसी भी चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले आंकड़ों का सही तरीके से मिलान करने और इस साल के लोकसभा चुनावों के फार्म 17सी, 20, 21सी, 21डी और 21ई की सूचना के साथ ही सारे भावी चुनावों की ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

छह राज्यों ने किया कानून लागू करने से इनकार

पेज 1 का बाकी
कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद में पारित करके और इसके कानून बना कर केंद्र सरकार हमें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन के मुद्दे पर हम पार्टी की लाइन मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमलोग उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहते, जिसका बीज भेदभाव हो। महाराष्ट्र में बाला साहेब थोरट ने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व की नीति का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस कानून पर

पार्टी नेतृत्व का निर्णय ही उनका भी निर्णय है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एलान किया था कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कहा कि उन्हें भी यह स्वीकार नहीं है। विजयन ने इसे असंवैधानिक बतायात हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में सतारूडू तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डेरेंक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके राज्य में एनआरसी और नागरिकता कानून दोनों ही लागू नहीं किए जाएंगे।

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंची निर्भया की मां

पेज 1 का बाकी
को उसी वक्त सुनी जाएगी जब दोषी की पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए आएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ जुलाई को इस मामले के तीन अन्य दोषियों 30 वर्षीय मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि वह निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी की सजा पर अमल करने के लिए जरूरी करार जारी करने की मांग की याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने यह देखते हुए कि दोषियों में से एक की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है, इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

पेज 1 का बाकी
के सभी पर्वतीय जिलों में जिला प्रशासन ने तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। नैनीताल में शुक्रवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। औली जोशीमठ, बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब रानीखेत में जम कर बफ गिरी। पर्यटक नैनीताल, रानीखेत, कौसाना, मसुरी, जोशीमठ और औली बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वही उत्तराखंड में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हो गए।

पहाड़ों में मौसम ने अचानक करवट बदली और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरराज्य कड़ाके की

सदी की चपेट में है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, हरकिदून घाटी के दर्जनों गांवों में करीब 10 से 15 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। यमुना घाटी में भी बर्फबारी लगातार जारी है। यमुना जी का मंदिर भी बर्फ की चपेट में आ गया है। नैनीताल में शीतकाल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। देर रात बरसात होने के बाद तड़के सवेरे बर्फबारी हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के बाद गुरुवार को मौसम का पहली बर्फबारी देखने को मिली। नैनीताल का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग बंद पड़ा है। यमुनोत्री राजमार्ग राड़ी टॉप व गंगोत्री राजमार्ग चंपावत

की कई सड़कें बंद पड़ी हैं। कुमाऊं मंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक जगत राम जोशी का कहना है कि सभी जिलों में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी शनिवार तक बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से कहीं नुकसान हो रहा है तो वही दूसरी तरफ सेब और चावल की खेती करने वाले किसानों को फायदा हुआ है।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, हेमकुंड नैनीताल, पिथौरागढ़, मुंसियारी, टिहरी, पौड़ी, औली जोशीमठ, चमोली समेत पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान शून्य से नीचे चला गया है। उत्तराखंड के चारों धर्मों को बर्फ की चादर ने ढक दिया है।

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

नहीं जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में संशोधित नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को बेलाडोंगा स्टेशन का आग लगा दी और वहां तैनात आरपीएफ कर्मियों के साथ मारपीट की। कई अल्पसंख्यक संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पर उतरें हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, ‘नैनीताल में शुक्रवार के दो राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। असम और मेघालय में इंटरनेट और ट्रेन सेवाएं टप हैं। इस बीच, प्रदर्शन और हिंसा की शुक्रवार को पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में एक रेलवे स्टेशन फूंक दिया। राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा के उलूबेडिया में छह घंटे से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग छह जाम कर दिया गया। फ्रंस ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर उन्हें असम और त्रिपुरा

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

पेज 1 का बाकी
की रोक नहीं है लेकिन यह भी सही है कि यह अभी अंतिम नहीं है। पीठ ने कहा कि सात सदस्यीय पीठ को सौंपे गए मुद्दों पर फैसला आने के बाद जल्द से जल्द पिछले साल सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसने कहा कि वह वृहद पीठ का निर्णय आने तक इस मामले में कोई आदेश नहीं देगा और यदि मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं का सहर्ष स्वागत किया जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी।

एक याची के वकील ने जब जोर देकर कहा कि पिछले साल के निर्णय पर अदालत ने

रोक नहीं लगाई है तो जजों ने कहा-हम जानते हैं कि कानून आपके पक्ष में है और यदि इसका पालन किया गया और इसका उल्लंघन हुआ तो हम लोगों को जेल भेजेंगे। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही एक महिला कार्यकर्ता की ओर से विरष्ट वकील कोलिन गोन्साल्विज ने कहा कि केरल सरकार महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है और यह पिछले साल के फैसले पर रोक जैसा ही है हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने कहा- इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में एक फैसला है। इस बारे में भी कोई संदेह नहीं है कि मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है। मैंने अभी तक वृहद

पीठ गठित नहीं की है। सहूलियत के संतुलन के लिए जरूरत है कि हम आज कोई आदेश नहीं दें। यदि मामले का फैसला आपके पक्ष में हुआ तो हम इसे लागू करेंगे। गोन्साल्विज ने जब यह कहा कि मंदिर जाने वाली महिलाओं को पुलिस संरक्षण का आदेश दिया जा सकता है तो पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि स्थिति विस्फोटक हो।

जजों ने कहा- हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। हम फैसला लेंगे। इसमें संदेह नहीं कि फैसला आपके पक्ष में है लेकिन यह भी सही है कि यह अंतिम नहीं है।

राहुल का माफी मांगने से इनकार

पेज 1 का बाकी
राहुल गांधी मौजूद थे। सदन में नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12:15 बजे के तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही भाजपा की कई महिला सदस्य अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगीं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद पर 2001 में आज के दिन हुए आतंकी हमले की घटना का जिक्र किया और सदन ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

खबर कोना



भारत-वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले से पहले शुक्रवार को चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की दौड़ में

मेलबर्न, 13 दिसंबर (एफपी)।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने महिला फुटबल विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी का दावा पेश किया है। फीफा इस विश्व कप में टीमों की संख्या 22 से बढ़ाकर 24 करने की सोच रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दो देशों के मेजबान होने से अतिरिक्त मैचों के आयोजन में मदद मिलेगी। फीफा के अनुसार अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानी की दौड़ में हैं। मेजबानी पर फैसला मई में लिए जाने की संभावना है।

अंडर-17 महिला फुटबल : स्वीडन से 0-3 से हारी भारतीय टीम

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की अंडर-17 महिला टीम ने तीन देशों के फुटबल टूर्नामेंट में अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की और उसे शुक्रवार को यहां अपने पहले मैच में ही स्वीडन से 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्वीडन की टीम ने भारतीयों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उसकी तरफ से माल्टिडा विनबर्ग (चौथे मिनट), इडा वीनडेनबर्ग (25वें मिनट) और मोनिका जुसु बाह (90+1 मिनट) ने गोल किए। स्वीडन को चौथे मिनट में ही पेनल्टी किंग मिली जिसे विनबर्ग ने गोल में बदला। स्ट्राइकर बाह को पेनल्टी बाक्स में गिराए जाने के कारण स्वीडन को यह पेनल्टी मिली थी।

पीसीबी का अशरफ, शिनवारी को एनओसी देने से इनकार

कराची, 13 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हरफनमौला फहीम अशरफ और तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी को आस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने से इनकार कर दिया। अशरफ और शिनवारी ने हाल ही में बीबीएल के साथ करार किया था। अशरफ ने मई के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उनके साथ मेलबर्न रेनेगेड्स ने करार किया था जबकि शिनवारी को इसी टीम ने पहले पांच मैचों के लिए अनुबंधित किया है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि अशरफ को घरेलू क्रिकेट पर फोकस करने के लिए कहा गया है जबकि शिनवारी को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम में चुना गया है।

आइपीएल नीलामी का हिस्सा बनेंगे 332 खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में कोई भारतीय नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए होने वाली नीलामी के लिए 332 खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली यह नीलामी की प्रक्रिया पहली बार सुबह की जगह दोपहर (3:30) में शुरू होगी। नीलामी में भाग लेने के लिए 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने खुद को सबसे ज्यादा दो करोड़ रुपए वर्ग में रखा है।

दो करोड़ की सूची में पांच आस्ट्रेलियाई दो करोड़ रुपए के बेस प्राइस की सूची में सात खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इसमें से पांच आस्ट्रेलियाई हैं। दिलचस्प यह है कि टी-20 विश्व कप की तैयारी में जुटी टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी का नाम इस सूची में नहीं है। सभी खिलाड़ी विदेशी हैं। आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस लिन, पैट कर्मिस, जोश हेजलवुड और मिशेल मार्श शामिल हैं। वहीं श्रीलंका के हरफनमौला एंजेलो मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने भी खुद को इस सूची में रका है।

उथप्पा पर होगी सभी की निगाहें
इस बोली में सिर्फ 73 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें केवल 29 विदेशी शामिल होंगे। फिच एक करोड़ रुपए के खिलाड़ियों की सूची में हैं। केकेआर से रिलीज किए गए आस्ट्रेलिया के क्रिस लिन को इस बोली में अच्छी कीमत

1.5 करोड़ की सूची में अकेले भारतीय उथप्पा

डेढ़ करोड़ की बेस प्राइस में कुल दस खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इसमें एकमात्र भारतीय रॉबिन उथप्पा हैं। बाकी नौ खिलाड़ी विदेशी हैं। इंग्लैंड के चार खिलाड़ियों ने इस सूची में जगह बनाई है। इसमें ईयान मॉर्गन, जैसन रॉय, क्रिस वोक्स और डेविड विली शामिल हैं। आस्ट्रेलिया के एडम जंपा, शॉन मार्श और केन रिचर्डसन नीलामी में भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम से काइली एबॉट और क्रिस मारिस इस बेस प्राइस सूची का हिस्सा हैं।

आइपीएल की आगामी सत्र के लिए शुरुआत में 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। आठ फ्रेंचाइजियों से मिले चयनित खिलाड़ियों की सूची के बाद इसे छोटा कर दिया गया।

मिलने की उम्मीद होगी। उथप्पा के आलवा जिन भारतीय खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों की नजर होगी उसमें पीयूष चावला (केकेआर),



युसूफ पटान (सनराइजर्स हैदराबाद) और जयदेव उनादकट (राजस्थान रॉयल्स) शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी एक करोड़ रुपए की सूची

दो करोड़ की सूची में शामिल खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में सात खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सभी सात खिलाड़ी विदेशी हैं। इन खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल, पैट कर्मिस, जोश हेजलवुड, मिशेल मार्श, डेल स्टेन और एंजेलो मैथ्यूज।

भारतीय खिलाड़ियों की कीमत

1.5 करोड़ : रॉबिन उथप्पा
1 करोड़ : पीयूष चावला, युसूफ पटान, जयदेव उनादकट
50 लाख : चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, स्टुअर्ट बिन्नी, मोहित शर्मा
20 लाख : पवन देशपांडे, यशस्वी जायसवाल

में हैं। नीलामी में 186 भारतीय खिलाड़ी जबकि 143 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ी शामिल हैं।

मानसिक रूप से थक चुका था : मैक्सवेल

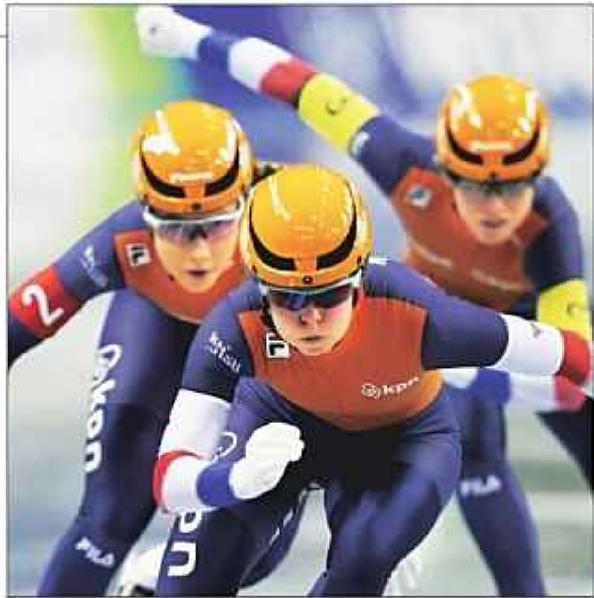
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि पिछले चार या पांच साल से लगातार खेलते रहने के कारण वह मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक चुके थे। इसी कारण उन्हें अक्टूबर में मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आराम लेने को मजबूर होना पड़ा। मैक्सवेल श्रीलंका के खिलाफ पहले दो मैच खेलने के बाद अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हट गए थे।

उन्होंने कहा कि जब मैंने हटने का फैसला किया तो मैं काफी थका हुआ था। मैंने आराम लेने का फैसला क्यों किया इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह थक चुका था। मैं लगातार आठ महीने से व्यस्त था और पिछले चार पांच वर्षों से ऐसा हो रहा था। मैं लगातार खेल रहा था और उस समय यह थकान मुझ पर हावी हो गई थी।

उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में क्रिकेट आस्ट्रेलिया, क्रिकेट विक्टोरिया और स्टार्स का आभार व्यक्त करना चाहता जिन्होंने मुझे खेल से बाहर रहने की अनुमति दी। मुझे सही स्थिति में लौटने के लिए समय दिया। मैक्सवेल ने कहा कि वह उनकी महिला मित्र थी जिसने सबसे पहले उनमें बदलाव महसूस किया।

उन्होंने कहा कि असल में वह मेरी महिला मित्र थी जिसने मुझे किसी से सलाह लेने के लिए कहा। सबसे पहले उन्हें मेरे अंदर बदलाव का अहसास हुआ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शुरुआती बातचीत के बाद ही मुझे लगा कि जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया।



जापान के नगानो में स्पीड स्केटिंग विश्व कप में महिला स्प्रिट रेस के दौरान मुकाबला करती खिलाड़ी।

कपूर सात अंडर के शानदार कार्ड से संयुक्त पांचवें स्थान पर

जकार्ता, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर शिव कपूर इंडोनेशिया मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दिन शुक्रवार को सात अंडर 65 का शानदार कार्ड खेलकर संयुक्त पांचवें स्थान पर पहुंच गए। कपूर दूसरे दिन उन पांच गोल्फरों में शामिल रहे जिन्होंने दिन का सर्वश्रेष्ठ सात अंडर का कार्ड खेला। उन्होंने गुरुवार को पहले दौर में दो अंडर 70 का कार्ड खेला था जिससे उनका कुल स्कोर नौ अंडर का है। शीर्ष दस में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अजितेश

संधू भी है। पांच अंडर 67 का कार्ड खेलने वाला यह गोल्फर कुल आठ अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से आठवें पायदान पर है। राशिद खान ने भी दूसरे दौर में सात अंडर का शानदार कार्ड खेला। वह छह अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर है। विराज मदप्पा (तीन अंडर 69) भी इसी पायदान पर है। कट हासिल करने वाले अन्य भारतीयों में ज्योति रंधावा (तीन अंडर 69) संयुक्त 30वें, एसएसपी चौरसिया (तीन अंडर 69) संयुक्त 39वें, अमन राज (एक ओवर 73) संयुक्त 50वें और अर्जुन अटवाल (एक अंडर 71) संयुक्त 60वें स्थान पर है।

तनसीम क्वार्टर फाइनल में, वरुण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप से बाहर

सुराबाया (इंडोनेशिया), 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की तनसीम मीर ने एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में शुक्रवार को लड़कियों के अंडर-15 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया लेकिन वरुण कपूर लड़कों के अंडर-17 वर्ग से बाहर हो गए। गुजरात की तनसीम ने मलेशिया की वेन सी चान को केवल 20 मिनट में 21-6, 21-16 से हराया। उनका अगला मुकाबला जापान की माया तागुची से होगा।

लड़कों के अंडर-17 एकल में महाराष्ट्र के वरुण कपूर को इंडोनेशिया के रायनाल्डी ओक्टाविनो रिज्की से 19-21, 21-23 से हार का

सामना करना पड़ा। असम के तन्मय विकास बरुआ ने हालांकि अंडर-15 डेनमार्क के फारेल सतरिया परडाना को 24-22, 21-15 से पराजित किया।

बरुआ ने लक्ष्य शर्मा के साथ अंडर-15 युगल में थाईलैंड के तनाकोर्न मीचा और टाइनुकुन तियाचान को 21-18, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लोकेश रेड्डी और अंकित मंडल की जोड़ी भी अंतिम आठ में पहुंच गई है। लड़कियों के युगल में आंद्रिया सराह कुरियन और पवित्रा नवीन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा

अंडर-17 वर्ग में जनानी अनंतकुमार और तान्या हेमंत की जोड़ी आगे बढ़ने में सफल रही।

मैच के आधार पर तय होगी रैंकिंग

लुसाने, 13 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने शुक्रवार को 2020 के लिए नई विश्व रैंकिंग प्रणाली का अनावरण किया। इसमें रैंकिंग का निर्धारण टूर्नामेंट के आधार पर नहीं बल्कि मैच के आधार पर होगा। नई व्यवस्था अगले साल एक जनवरी से लागू होगी। एफआइएच ने कहा कि बारह महीने के गहन शोध, विश्लेषण और परीक्षण के बाद यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।

2003 से जारी एफआइएच विश्व रैंकिंग प्रणाली मूल रूप से टूर्नामेंटों में टीमों को पूल में बांटने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत टीमों को साल में दो या तीन बार रैंकिंग अंक बनाने का मौका मिलता था। इससे निचली रैंकिंग वाली टीमों के पास कम मौके रह जाते थे और उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता था एफआइएच ने एक बयान में कहा कि करीब 60 फीसद अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई रैंकिंग अंक नहीं होते और यही देखकर हमें बदलाव करना पड़ा। नई प्रणाली के तहत एफआइएच से मान्यता प्राप्त हर मैच के लिए टीमों को रैंकिंग अंक मिलेंगे।

बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में बंगलुरु ने पैथर्स को हराया

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

बंगलुरु ब्रॉलर्स ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (आइबीएल) में चढ़ा उलटफेर करते हुए पंजाब पैथर्स को 4-3 से हराया। अनामिका (51 किग्रा) और कप्तान सिमरनजीत (60 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर बंगलुरु को अच्छी शुरुआत दी। इनके अलावा दिनेश डगगर ने चार मैचों में आज अपना पहला मैच जीता जबकि पवन

कुमार ने भी चार मैचों में पहली जीत दर्ज की।

अभी तक अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 12 अंक जुटा चुकी पैथर्स ने इस मैच में चार मुक्केबाजों को लीग में पदापण का मौका दिया। टीम ने कप्तान एमसी मैरी काम, उज्ज्वलिका के अब्दुलमलिक खालाकोव, मनोज कुमार को आराम दिया। इस हार से पैथर्स अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। पैथर्स के चार मैचों से 15 अंक हो गए हैं वह गुजरात जाएंट्स से पीछे हैं जिसके चार मैचों में 17 अंक हैं।

सिंधू ने बिंगजियाओ को हरा अभियान का अंत किया

ग्वांगजू, 13 दिसंबर (भाषा)।

खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधू ने गुप ए के अपने तीसरे और अंतिम मैच में चीन की ही बिंगजियाओ पर सांत्वना जीत दर्ज करके वर्ष के आखिरी टूर्नामेंट

बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल में अपने अभियान का सकारात्मक अंत किया। पिछले साल की चैंपियन सिंधू अपने पहले दोनों मैच गंवाने के कारण खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थी। बिंगजियाओ के खिलाफ भी पहले गेम में वह 9-18 से पीछे चल रही थी लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे से पहले

नेट पर गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

कमर की चोट के बाद रिहैबिलिटेशन में जुटे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले नेट पर भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की शुरुआत से टीम से बाहर हैं। वह हालांकि अब ठीक होने की राह पर हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले साल न्यूजीलैंड दौरे से पहले वह फिट हो जाएंगे।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि बुमराह भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। अब यह परंपरा बन गई है। टीम प्रबंधन ने भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस भी इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ टैस्ट से पहले परखी थी हालांकि वह टीम का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह बुमराह की फिटनेस को आजमाया जाएगा। सूत्र ने कहा कि अब यही परंपरा बन गई है कि जब कोई खिलाड़ी फिट होता नजर आता है तो टीम प्रबंधन, फिजियो और ट्रेनर नेट अभ्यास में उसे परखते हैं। बुमराह और हादिक पंड्या आइपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई के बीकेसी मैदान पर उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। ऐसी भी संभावना है कि बुमराह को भारत 'ए' टीम के साथ न्यूजीलैंड भेजा जाए ताकि उन्हें अभ्यास मिल सके।

कुंबले बोले, अय्यर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले का मानना है कि श्रेयस अय्यर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाजों के लिए यह श्रृंखला चुनौतीपूर्ण होगी। कुंबले ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज के मजबूत विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ

प्रदर्शन करना होगा।

उन्होंने कहा कि विश्वर के नहीं होने से केएल राहुल को पारी के आगाज का मौका मिला है। श्रेयस अय्यर काफी परिपक्व बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह चौथे नंबर पर उतरें। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि वेस्ट इंडीज के सामने गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होगी। उनके पास दमदार हिटर्स हैं। गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज के मजबूत विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो बल्लेबाजी क्रम को उम्दा प्रदर्शन करना होगा।



चोटिल भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर

चेन्नई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोटिल होने के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मुंबई के तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर को टीम में जगह मिल सकती है। भुवनेश्वर बुधवार को समाप्त हुई टी20

अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे।

बीसीसीआइ के अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, 'भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और शारदुल टीम में उनकी जगह लेंगे।' शारदुल बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की टीम में थे और गुरुवार तक उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ रणजी मैच में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था।